*Research Journal of Language, Literature and Humanities* E-ISSN 2348-6252
Vol. **3(6),** 8-14, June **(2016)** *Res. J. Lang. Lit. Humanities*

# ग्रामीण विकास मे सामुदायिक रेडियो की भूमिका: एक अध्ययन

**मनीष कुमार जैसल**
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय वर्धा 442001
mjaisal2@gmail.com

**Available online at: www.isca.in, www.isca.me**
Received 16th March 2016, revised 29th April 2016, accepted 14th May 2016

## शोध सारांश

एक ऐसा रेडियो केन्द्र जो कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, सामुदायिक विकास, संस्कृति सम्बन्धी कार्यक्रमों के प्रसारण के साथलिक प्रासंगिता के कार्यक्रमों का प्रसारण करता हैसाथ समुदाय के लिए तात्का-| सामुदायिक रेडिओ की संज्ञा दी जा सकती हैं| सामुदायिक रेडियो को किसी एक परिभाषा में बाँधना सम्भव नहीं है। प्रत्येक देश के संस्कृति सम्बन्धी क़ानूनों में अन्तर होने के कारण देश और काल के साथ सामुदायिक रेडियो की परिभाषा बदल जाती है। फ्रांस, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड जैसे कई देशों में एक विशिष्ट प्रसारण क्षेत्र के रूप में सामुदायिक रेडियो की परिभाषा के भाग के रूप में ज्यादातर कानूनों में सामाजिक लाभ, सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक प्राप्ति जैसे वाक्यांश शामिल किये गये हैं। किन्तु मोटे तौर पर किसी छोटे समुदाय द्वारा संचालित, कम लागत वाला रेडियो स्टेशन जो किसी समुदाय के हितों, उसकी पसंद और उनके विकास के दृष्टिकोण को रखते हुए ग़ैरव्यावसायिक प्रसारण करता है, सामुदायिक रेडियो केन्द्र कहलाता है |21वीं सदी मे मीडिया की बाढ़ सी आ गयी ऐसे मे सामुदायिक रेडियो के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसके अव्यवसायीकता को लेकर होती नज़र आती हैं| आज भारत में जहां एक तरफ मीडिया हर साल तरक्की की नई नई ऊंचाईयां छू रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी आबादी सामुदायिक रेडियो के नाम से भी परिचित तक नहीं है । कई जानकार इसका कारण सामुदायिक रेडियो के दायरे छोटा होना और दूसरे इसे चलाने और इससे फायदा पाने वालों का बेहद आम और स्थानीय होना बताते हैं| भारत के संदर्भ मे हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस रेडियो की ताकत हमारी और आपकी सोच से भी परे है। क्योंकि इसका संचालक, कार्यकर्ता और उपभोक्ता वो तबका है जो इस देश की चुनाव प्रक्रिया में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। प्रस्तुत शोध पत्र में हम सामुदायिक रेडियो का ग्रामीण विकास मे होने वाले योगदान पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए वर्तमान मे विभिन्न प्रान्तों मे सक्रिय सामुदायिक रेडियो की भूमिका को जानने की कोशिश करेंगे |

**शब्द कुंजिया**: सामुदायिक रेडियो,ग्रामीण विकास, मीडिया

## प्रस्तावना

इन पांच बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित कर ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं को समझा जा सकता है । इसमें पहला बिन्दु है- शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य जागरण केन्द्रित कार्यक्रम और तीसरा- कृषि जिसमें खेती को जैविक कृषि की ओर मूल्यवर्धक प्रक्रिया से जोड़ा जाना है, चौथा है- सामाजिक वातावरण निर्माण करना, जिसमें महिला मंडलियों का गठन, मंदिर केन्द्रित ग्रामीण संरचना, वाचनालय, क्रीड़ा मंडली का गठन, क्रीड़ा प्रतियोगिताओं और ग्रामोत्सव का आयोजन, पांचवां- स्वावलंबन, जिसके अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह खड़े किए जाएं, ग्रामीण उद्योग धंधों को सशक्त बना उन्हे आधुनिक रूप दिया जाए[1]।

गांव के विकास का अर्थ है गांव अर्थात ग्रामीण आबादी को आत्मनिर्भर बनाया जाना और सरकार पर उसकी निर्भरता को नगण्य बनाना। उदाहरण के लिए गुजरात के एक गाँव को देखें जहां राजपीपला के पास साकवा गांव में ग्रामीणों के प्रयास से एक ऐसा विकास क्रम निर्माण हुआ है जो सबके लिए प्रेरक हो सकता है कि वहां नमक के अलावा कोई चीज शहर से नहीं मंगाई जाती। इतनी आत्मनिर्भरता वहां के ग्रामीणों ने अपने

गांव को उपलब्ध कराई है। वास्तव में यही ग्रामीण विकास की बेहतरीन संकल्पना हो सकती है।

विकास एक भारी भरकम सा शब्द सुनाई देता हैं इसी विकास के नारे के दम पर 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता गया | पिछले कई वर्षों में विकास शब्द का अर्थ लगातार बदल रहा हैं फिर भी आज के संदर्भ में विकास की व्यापक धारणा के अनुसार यह एक ऐसी स्थिति है जिसमे व्यक्ति अपने जीवन पर विशेष कर आय,स्वास्थ्य और साक्षरता में बदलाव ला सकें और अपना जीवन स्तर सुधार सकें |

**शोध प्रविधि: १.** प्रस्तुत शोध पत्र में अंतर्वस्तु विष्लेषण पद्धति का प्रयोग कर ग्रामीण विकास के विविध पहलुओं को जानते हुए वर्तमान मे चल रहे सामुदायिक रेडिओ की पहचान की जाएगी| २. इस शोध पत्र में विभिन्न मीडिया आलोचकों से साक्षात्कार भी किया गया है |

## सामुदायिक रेडियो

सामुदायिक रेडियो को किसी एक प्रमुख परिभाषा में बाँधना सम्भव नहीं है। प्रत्येक देश के संस्कृति सम्बन्धी क़ानूनों में अन्तर होने के कारण देश और काल के साथ इसकी परिभाषा बदल जाती है। किसी छोटे समुदाय द्वारा संचालित कम लागत वाला रेडियो स्टेशन जो समुदाय के हितों, उसकी पसंद और समुदाय के विकास को दृष्टिगत रखते हुए ग़ैरव्यावसायिक प्रसारण करता है, सामुदायिक रेडियो केन्द्र कहलाता है । ऐसे रेडियो केन्द्र जो कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, सामुदायिक विकास, संस्कृति सम्बन्धी कार्यक्रमों के प्रसारण के साथ-साथ समुदाय के लिए तात्कालिक प्रासंगिता के कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैसामुदायिक रेडियो की श्रेणी मे आते है। वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित की जा रही जागरूकता कार्यशालाएं सामुदायिक रेडियो के बारे में जागरूकता फ़ैलाने और प्रचार-प्रसार में काफी फायदेमंद साबित हो रहीं हैं | दुनिया के कई हिस्सों में, स्वयंसेवी क्षेत्र, नागरिक समाज, एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों और नागरिकों के लिए सामुदायिक रेडियो और अधिक सामुदायिक विकास तथा प्रसारण उद्देश्यों के कार्य में भागीदारी के माध्यम के रूप में काम करता है।

फ्रांस, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड जैसे कई देशों में एक विशिष्ट प्रसारण क्षेत्र के रूप में सामुदायिक रेडियो की महत्वपूर्ण कानूनी परिभाषा की गयी है। परिभाषा के भाग के रूप में ज्यादातर कानूनों में सामाजिक लाभ, सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक प्राप्ति जैसे वाक्यांश शामिल किये गये हैं।

भारत में पहली बार सामुदायिक रेडियो की शुरुआत आकाशवाणी के सहभागी के तौर पर भुज (गुजरात) में हुई लगभग 10 से 12 किमी तक की रेंज कवर करने वाले इस सामुदायिक रेडियो की जब नींव डाली गई थी, तब इसका मकसद ग्रामीण जनता की आवश्यकता, प्राथमिकता, समस्या, सुझाव और समाधान से जुड़ा था |[2]

**अभी मंजिल दूर हैं :** आज भारत में मनोरंजक मीडिया हर साल तरक्की की नई- नई ऊंचाईयां छू रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी आबादी सामुदायिक रेडियो के नाम से भी परिचित नहीं है। हालांकि इसकी वजहें कई हो सकती हैं । एक तो सामुदायिक रेडियो का दायरा बेहद छोटा होना और दूसरे इसे चलाने और इससे फायदा पाने वालों का बेहद आम और स्थानीय होना। लेकिन, इसके बावजूद हमें ये नहीं भूलाना चाहिए कि इस रेडियो की ताकत हमारी और आपकी सोच से भी परे है। क्योंकि इसका संचालक, कार्यकर्ता और उपभोक्ता वो तबका है जो इस देश की चुनाव प्रक्रिया में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है।

भारत में सामुदायिक रेडियो की लहर 90 के दशक में ही पैदा हो गई थी, जब 1995 में ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि '**रेडियो तरंगें जनता की संपत्ति हैं।**' हालांकि, यह एक अच्छी खबर जरूर थी, लेकिन शुरूआती दौर में सिर्फ शैक्षिक स्तर पर ही ऐसे स्टेशनों को खोलने की इजाजत मिली थी।

चेन्नई स्थित अन्ना विश्वविद्यालय का अन्ना एफएम पहला कैंपस सामुदायिक रेडियो बना, जिसके तमाम कार्यक्रम आज भी विश्वविद्यालय के छात्र ही तैयार करते हैं। लेकिन, नवंबर 2006 में जब भारत सरकार ने एक नई नीति के तहत गैर-सरकारी संस्थानों और दूसरी सामाजिक संस्थाओं को भी सामुदायिक रेडियो शुरू करने की इजाजत दे दी थी, उसके बाद से धीरे धीरे बदलाव नजर आने लगा।

**उदारीकरण के बाद का बदलाव:** वर्ष 1991 के आसपास जैसे ही उदारीकरण के नाम पर नए बाजार का उदय हुआ, देश में कई माध्यमों की अवधारणाओं का अंकुर फूट पड़ा. यह वह दौर था, जब प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सूचना का अधिकार जैसे माध्यम गांव तक बेअसर हो रहे थे, इन माध्यमों को प्रभावी बनाने के साथ-साथ बाज़ार में खड़ा करने की पुरजोर कोशिशों के बीच ही सामुदायिक रेडियो की अवधारणा पनपी | अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो सामुदायिक रेडियो का बीज 1940 के दशक में लैटिन अमेरिका में पड़ा था और दक्षिण एशिया में नेपाल पहला देश है, जहां 1997 में सामुदायिक रेडियो की शुरुआत हुई[3]

**विश्व मे सामुदायिक रेडिओ की शुरुआत:** जानकार मानते है कि अमरीका में सामुदायिक रेडियो की शुरूआत बीसवी सदी के चौथे दशक में हो गई थी । इसके पूर्व तीसरे दशक में, डेविड आर्मस्ट्राँग, एफएम प्रसारण का अविष्कार कर रेडियो प्रसारण के एक नए युग का सूत्रपात कर चुके थे । अपने शुरूआती दिनों में अमरीकी रेडियो का स्वरूप मुख्य रूप से व्यावसायिक था। एफएम रेडियो की संभावनाओं को पहचानने के पहले प्रयास के रूप में द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन द्वारा एफएम बैंड की निचली आवृतियों (881 मेगा हर्ट्ज़ से 919 मेगा हार्ट्ज़ तक) शैक्षणिक रेडियो के लिए सुरक्षित रखने का प्रावधान माना जाता हैं |

पहला सामुदायिक रेडियो केन्द्र 'वेस्ट कोस्ट' में लुइस हिल नाम के मशहूर पत्रकार द्वारा आरम्भ किया गया। 1946 में इससे जुड़े प्रसारणकर्ताओं ने "पेसिफिका फाउंडेशन" की स्थापना की। विश्व युद्ध के पश्चात् उस समय विभिन्न राष्ट्रों के बीच समझ पैदा करने को आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से पेसेफिका फाउंडेशन ने सामुदायिक रेडियो प्रसारण आरम्भ किया ।

**सामुदायिक रेडियो और एफएम चैनलों की संख्या बढ़ाने को लेकर नीति गठन:** केन्द्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्य वर्धन सिंह राठौर कहते है कि केन्द्र् सरकार रेडियो को लोकप्रिय बनाने के लिए सामुदायिक रेडियो और एफएम चैनलों की संख्याए बढ़ाने के लिए नीति तैयार कर रही है । राठौर ने कहा कि कम्युणनिटी रेडियो को बढ़ावा देने, एफ एम चैनल की लोकप्रियता बढ़ाने और पुराने आकाशवाणी केन्द्रों की क्षमता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं । उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है की सामुदायिक रेडियो के माध्यम से किसानों को मौसम और कृषि संबंधी जानकारी आसानी से पहुंचायी जा सकती है। सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने एक कार्यक्रम में बताते हैं कि "सामुदायिक रेडिओ और एफ एम चैनलों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए 100 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ एक स्कीम शुरू की जा रही है । यह स्कीम लगभग 600 नए व मौजूदा सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशनों की सहायता करेगी।" अभी देश में केवल 170 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं और 400 स्टेशनों के लाइसेंस सरकार की मंजूरी का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में इस क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन अच्छी खबर है। लेकिन उसके साथ कुछ पेंच हैं। पिछले साल, तब के वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भी इस क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। लेकिन सूत्रों के मुताबिक, यह धन वास्तविक विकास के बजाय केवल रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। मौजूदा 170 स्टेशनों में से ज्यादातर निजी या सरकारी शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। फिर कुछ ऐसे हैं जिन्हें एनजीओ या किसानों के समुदाय चला रहे हैं।

**कुल सामुदायिक रेडियो स्टेशन:** जुलाई 2014 तक के आंकड़ों के अनुसार 170 सामुदायिक रेडियो: १. प्रमुख सामुदायिक रेडियो स्टेशन: शिक्षा क्षेत्र (निजी व सरकारी) 85, २. एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे सामुदायिक रेडियो स्टेशन 61, ३. विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे सामुदायिक रेडियो स्टेशन 12, ४. राज्यों के कृषि सामुदायिक रेडियो स्टेशन 6, ५. कृषि विज्ञान केंद्रों के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 6, ६. सबसे ज्यादा सामुदायिक रेडियो स्टेशन तमिलनाडु 27, ७. उत्तर प्रदेश 19, ८. महाराष्ट्र 16. वहीं, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड व मणिपुर जैसे राज्य हैं जहां अभी तक एक भी सामुदायिक रेडियो स्टेशन नहीं है।

मुंबई के मस्ट रेडियो के संस्थापक पंकज अठावले कहते हैं, **"सामुदायिक रेडियो को सामाजिक बिजनेस की तरह प्लान करना चाहिए। आपको अपने स्टेशन की जरूरत के हिसाब से तमाम शैक्षणिक संस्थाओं या सामाजिक एजेंसियों से प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। लेकिन आज पूरा आंदोलन बहुत दार्शनिक होता जा रहा है और कोई विकास होता नहीं दिखता।"**

## कम्युनिटी रेडियो से लाभ पर होंगे शोध

सूचना एवं प्रसारण मंत्रलय देश में चल रहे कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों की स्थिति तथा उनके प्रभावों को जानने के लिए शोध करने कि नीति तैयार कर चुकी हैं यह इसलिए भी किया जा रहा है, ताकि भविष्य में इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके तथा समाज की मांग के अनुरूप सामुदायिक रेडिया का स्वरूप गढ़ा जा सके | अध्ययन के लिए मंत्रलय ने एक एजेंसी नियुक्त करने का फैसला किया है, जो सर्वे कर यह भी पता लगायेगी कि कम्युनिटी रेडियो के प्रसारण को कितने लोग सुनते हैं तथा इसकी पहुंच कितनी बड़ी आबादी तक है।[4]

## सामुदायिक रेडिओन के कार्यक्रम की रूपरेखा

सामुदायिक रेडियो किस तरह के कार्यक्रम प्रसारित करेगा, इसे लेकर कोई खास नियम कानून नहीं है. उससे केवल यह उम्मीद की जाती है कि वह केवल वैसे ही कार्यक्रम बनाए और उनका प्रसारण करे, तो समुदाय के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण, स्वरोजगार, ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास पर आधारित हो | 50 प्रतिशत कार्यक्रम समुदाय की भागीदारी से तैयार करनी है.

## सामुदायिक रेडिओ का बढ़ता ग्राफ

सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्वयंसेवी संगठनों की ओर से स्थापित किए जाते है | इनके कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों की कम से कम 50 फीसदी की भागीदारी होनी चाहिए. कम्युनिटी रेडियो को स्थापित करने पर औसतन 15 लाख रु. खर्च आता है. 2002 में सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों के कम्युनिटी रेडियो स्थापित करने के लिए नीति निर्धारित की थी| इस नीति को 2006 में एनजीओ या अन्य संस्थानों के लिए भी लागू कर दिया गया | इसके तहत संचालक अधिकतम 30 मीटर ऊंचा एंटीना और अधितकम 100 वाट प्रभावी रेडिएटेड क्षमता का ट्रांसमीटर लगा सकते हैं. इससे करीब 5-15 किमी की रेंज कवर होती है. देश का पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो चेन्नै की अन्ना यूनिवर्सिटी में फरवरी, 2004 में स्थापित हुआ था. तो पहला एनजीओ बेस्ड सामुदायिक रेडियो संघम था, जिसे 2008 में तेलंगाना के मेडक जिले में डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने स्थापित किया| केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक, 2004-07 तक देश में महज 28 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन थे, जो 10 जून, 2015 तक बढ़कर 184 पहुंच गए|

एक ग़ैर सरकारी आंकड़े के मुताबिक, कम्युनिटी रेडियो के ज्यादातर लाइसेंस प्राइवेट सेक्टर के गिने-चुने मीडिया ग्रुपों को ही दिए गए हैं| पिछले साल तक सरकार ने एफएम चैनल चलाने के लिए अलग-अलग राज्यों के लगभग 100 शहरों में विभिन्न कंपनियों को लगभग 350 लाइसेंस बांटे| इस बंदरबांट में लाइसेंस बड़े संस्थानों की ही झोली में गए और छोटे समूह अपनी जगह भी नहीं बना पाए यानी उन्हें कोई भागीदारी नहीं मिली| रेडियो के इस कारोबार को विदेशी कंपनियां अपने कब्जे में लेने के लिए उतावली हैं| लाभ कमाने के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश के लिए मीडिया संस्थान आगे आ रहे हैं और इसके लिए सामुदायिक रेडियो के नाम पर एफएम को प्रोत्साहित किया जा रहा है |

## सूचना क्रांति के नए युग मे सामुदायिक रेडियो की भूमिका

पूरी दुनिया में सामुदायिक रेडियो ने जागरूकता पैदा करने और लोगों के विकास में सहयोग देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है| हालांकि रेडियो शुरुआत से मनोरंजन, ज्ञान एवं सूचना का पहला लोकप्रिय श्रव्य माध्यम रहा है | आज सूचना क्रांति का दौर है और रेडियो ऐसा माध्यम है, जो एक आम आदमी की पहुँच में है और जनसाधारण को जागरूक करने का कार्य करता है | रेडियो ने न केवल सूचना बल्कि शिक्षा जगत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है| रेडियो चैनलों की बढती मांग को देखते हुए मनोरंजन के साथ भरमार में सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) पिछले लगभग एक दशक से स्थानीय संचार के रूप में एक बहुत सुदृढ़ साधन बन कर उभरा है | ग्रामीण विकास, कृषि, स्वास्थ्य पोषक आहार, शिक्षा तथा पंचायती राज जैसे मुद्दों के बारे में सूचना प्रसारित करके ये रेडियो स्टेशन विकास प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं और सरकार इनके जरिये लाभार्थियों तक पहुँच सकती हैं।[5]

## वर्तमान में चले रहें सामुदायिक रेडिओ

**रेडियो रिमझिम: मेगा हर्ट्ज, स्थान :-** गोपालगंज,बिहार, **संचालक :-** अयोध्या लाल कल्याण निकेतन, **दायरा** :- 15

किमी, 200 गाँव, 5 लाख आबादी, **उद्देश्य** :- 2009 से बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के अलावा खेती,स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर कार्यक्रम प्रस्तुत करना

**रेडियो जामिया 90.4 मेगा हर्ट्ज: स्थान :** जामिया नगर दिल्ली, **संचालक** ; जामिया मिल्लिया इस्लामिया, **दायरा**: यूनिवर्सिटी के आसपास 10 किमी, **खासियत**; यूनिवर्सिटी के अलावा स्थानीय लोगो के लिए शांतिपूर्ण समाज का लक्ष्य निर्धारण करना, **असर** " स्लम एरिया मे स्वास्थ्य को लेकर काम

**रेडियो तिलोनिया, 90.4 मेगा हर्ट्ज: संचालक:-** सोशल वर्क्स एंड रिसर्च सेंटर, **दायरा:** 15-20 किलो मीटर 30 गाँव 50,000 आबादी, **उद्देश्य:** ग्राम सभा,पेंशन नरेगा,आरटीआई जैसी सरकारी योजनाओं की जानकारियाँ देना और मारवाड़ी मे खबरें प्रसारित करना, **असर**: ग्राम विकास अधिकारी, तहसीलदार,डॉक्टर बैंक मैनेजर और पोस्टमास्टर जैसे सरकारी कर्मचारी भी इसके कार्यक्रम मे शम्मिलित होकर सूचनाएँ देते हैं|

**रेडियो बुंदेलखंड 90.4 मेगा हर्ट्ज: स्थान;-** ओरछा बुंदेलखंड मध्यप्रदेश, **संचालक**;- तारा सामाजिक संस्था, **दायरा**;- 15-20 किलो मीटर, 30 गाँव,50,000 आबादी, **खासियत**:- स्थानीय भाषा में भी खबरें प्रसारित होती है, ग्रामसभा, पेंशन,नरेगा आरटीआई पर कार्यक्रम होते हैं | **असर**:- इसके कार्यक्रमों से प्रेरित होकर स्थानीय किसान खेती के लिए जैविक विधियाँ अपना रहे हैं स्थानीय महिलाएं भी सशक्त हो रही हैं |

**रेडियो किसान, 90.8 मेगा हर्ट्ज: स्थान:** बालिपटना खुर्दा ओड़ीशा, **संचालक**: एसोसिएशन फॉर इंट्रीग्रेटेड डेवलपमेंट, **दायरा**: 15-20 किमी, 212 गाँव, 3 लाख आबादी, **खासियत**; किसानों, वंचितों के लिए कार्यरत, **असर**: हुडहुद के दौरान स्थानीय लोगो की सूचना का जरिया बना किसानों की मदद करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2015 मे पुरस्कृत

**रेडियो नगर 90.4 मेगा हर्ट्ज: स्थान :** अहमदनगर महाराष्ट्र, **संचालक:-** स्नेहालय फाउंडेशन, **दायरा**:- 25 किमी, करीब ढाई लाख आबादी, **खासियत;-** वंचित बच्चों, वेश्याओं और उनके बच्चों, एचआईवी पीड़ितों के लिए काम, **असर**;- तुमचा आवाज कार्यक्रम लोकप्रिय हुआ

## मोबाइल-वेब रेडियो

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के निघासन के रहने वाले सपा समर्थक 30 वर्षीय धरमू यादव ने पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के पैतृक गांव सैफई से रेडियो सैफई नामक कम्युनिटी रेडियो शुरू करने की तैयारी की और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय में लाइसेंस के लिए आवेदन किया तो केंद्र सरकार ने अनुमति नहीं दी | तब वे इसी नाम से वेब रेडियो शुरू करने में जुट गए. उन्होंने इसके लिए तीन लाख रु. में स्ट्रीमिंग मशीन खरीदी और वेब प्रसारण के लिए नोएडा की कंपनी से 10,000 से 12,000 रु. प्रति माह की दर से सर्वर किराए पर लिया और रेडियो सैफई शुरू कर दिया| सपा सरकार कि रणनीति और विकास-विस्तार को फैलते धरमू यादव के रेडियो सैफई का उदघाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया |

इसी तरह शुभ्रांशु चैधरी ने 2010 में छत्तीसगढ़ में मोबाइल पर आधारित सीजीनेट स्वर की शुरुआत की थी और यह मोबाइल-वेब रेडियो अब छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना समेत आसपास के राज्यों के आदिवासियों की आवाज बन गया है. इसमें कोई भी स्थानीय व्यक्ति अपनी समस्या मोबाइल में रिकॉर्ड करके भेजता है और मोबाइल पर ही दूसरों की खबरें भी सुन सकता है. खबरों को स्वर वेबसाइट पर भी लोड कर दिया जाता है. मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भी ग्रीनपीस इसी तर्ज पर रेडियो संघर्ष चला रहा है. इसमें कम्युनिटी रेडियो की तरह रेंज की कोई सीमा नहीं है और इसे कहीं भी सुना जा सकता है.

## प्रमुख वेब रेडियो

**रेडियो सैफई: स्थान:** लखनऊ उत्तर प्रदेश, **संचालक**:- सपा समर्थक धरमू यादव, **दायरा**:- वेब रेडिओ, **खासियत**:- सपा की उपलब्धियों और उसकी सरकार की जानकारियाँ देता हैं |

**रेडिओ संघर्ष: स्थान**:- सिंगरौली मध्यप्रदेश मे मुख्य रूप से केन्द्रित, **संचालक**:- ग्रीन पीस एनजीओ, **दायरा** :-मोबाइल वेब रेडियो, **खासियत:-** स्थानीय महान जंगल के आदिवासियों के संघर्ष और समस्याओं को मंच देने के लिए स्थापित, **असर:-** स्थानीय लोग अपनी समस्याए मोबाइल मे रिकॉर्ड कर प्रासरित करते हैं |

**सीजीनेट स्वर: स्थान :-**गोंडवाना इलाका, **संचालक** :-शुभ्रांशु चौधरी,नाइट इन्टरनेशनल जर्नलिज़्म फ़ेलोशिप के तहत शुरू, **दायरा:-** मोबाइल वेब रेडियो, **खासियत:-** मुख्य धारा की दुनिया से महरूम आदिवासियो की आवाज बनने के लिए, **असर:-** आदिवासी अपनी समस्याए तथा समाधान प्राप्त करते है |

## निष्कर्ष

बड़े ही सार्थक उद्देश्य के साथ शुरू की गई सामुदायिक रेडियो की परिकल्पना व्यवसायिकता के चलते अस्तित्व के संकट से अब भी जूझ ही रही है| एक तरफ दूरदराज के इलाक़ों में राघव जैसे अनपढ़ ग्रामीण अपने दम पर कम्युनिटी रेडियो चला रहें हैं तो दूसरी ओर सरकार और कॉरपोरेट कंपनियां लाइसेंस की हेराफेरी करके इसके ज़रिए अपने व्यवसायिक हित साधने में लगी हुई हैं | बिना किसी सरकारी मदद के राघव ने अपने दम पर राघव ने एक साल के दौरान इकट्ठे किए हुए यंत्रों और उपकरणों के साथ रेडियो स्टेशन शुरू किया था| यह स्टेशन मुजफ्फरपुर, वैशाली और सारण ज़िलों में एक सामुदायिक रेडियो सेवा संचालित करता था| इस पर स्थानीय बोली में स्थानीय ख़बरें, गीत, एड्स जागरूकता, पोलियो उन्मूलन, गुमशुदगी की खबरें, साक्षरता पहल से संबंधित कार्यक्रम और इलाक़े में हो रहे अपराधों की सूचना आदि का नि:शुल्क प्रसारण किया जाता था|

इतना ही नहीं राघव के सामुदायिक रेडियो की बढ़ती लोकप्रियता को देख 2006 में केंद्रीय संचार मंत्रालय ने राघव से चैनल की वैधानिकता पर रिपोर्ट मांगी तो लाइसेंस न होने पर ज़िला अधिकारियों ने भारतीय टेलीग्राफ क़ानून के उल्लंघन के आरोप में राघव का रेडियो बंद करने के साथ राघव को दोषी मानकर गिरफ़्तार भी किया| ऐसे मे भारत सरकार द्वारा द्वारा सामुदायिक रेडिओ के प्रचार- प्रसार की नीतियाँ फाइलों मे कैद ही नज़र आती है | इतना सब होने के बाद भी वर्तमान में राघव राजस्थान के अजमेर ज़िले में एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन बेयरफुट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में परियोजना प्रमुख के तौर पर काम कर रहे हैं और भारत सरकार सिर्फ नीति पर नीति बनाकर सारे लाइसेंसों को पूँजीपतियों के हाथों मे रखती जा रही हैं | नतीजतन राघव जैसे समाज सेवीयों को खुद को विस्तार देना चाहिए वहीं देश के अमीरों की गुलामी करते कई राघव देखे जा सकते हैं |

## संदर्भ सूची

1. rajesh Kr. yadav, रेडियो किसके लिए, ब्लॉग, http://saranshsaar.blogspot.in/2010/09/blog-post.html . 30 july 2015
2. राजेश कुमार, सामुदायिक रेडियो सरकार और बाजार के : सी गरीबों की आवाजबीच फं, न्यूज़ पोर्टल http://www.allrights.co.in/samudayik-radio-aur-sarkar/ 25 july 2015
3. सरोज कुमार, कम्युनिटी रेडियोआवाज से बदलती जिंदगी :, [न्यूज़ पोर्टल[ http://aajtak.intoday.in/story/changing-the-local-world-through-community-radios-1-824884.html 2015 जुलाई 27
4. चौपालखबर, [न्यूज़ पोर्टल[ Rakesh Dhoundiyal, सामुदायिक रेडियोएक नए युग की शुरुआत :, http://samvadsamay.blogspot.in/2008/08/blog-post_23.html 30 july 2014
5. रवीद्र कुमार, सामुदायिक रेडियो की वापसी, न्यूज़ पोर्टल http://www.chauthiduniya.com/2010/09/samudayik-redio-aakhir-kiske-liye.html#sthash.h0xQL8Z3.dpuf 30 june 2015
6. टेलीविजन पोस्ट टीम,भारत में कब और कैसे चहक पाएंगे हज़ार सामुदायिक रेडियो स्टेशन, [न्यूज़ पोर्टल[, http://hindi.televisionpost.com/printradio/will-a-thousand-community-radio-stations-bloom-in-india/ | Hindi TelevisionPost, 5 जुलाई 2015
7. मुकुल श्रीवास्तव, रेडियो का खुलासा ब्लॉग http://mukulmedia.blogspot.in/2013_02_01_archive.html#.VqZoLPl97IX 26 july 2015
8. https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0% 30 july 2015

9. https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0% वेबसाइट, 30 july 2015

10. डुनावे, पीएच.डी., डेविड )2002। जनकोस्की(, निकोलस डब्ल्यू; Prehn, ओले। एड्स। "21 वीं सदी की शुरुआत में सामुदायिक रेडियो "व्यवसायीकरण बनाम समुदाय पावर : परिप्रेक्ष्य :चना युग में सामुदायिक मीडिया। सू(पीडीएफ) ) और संभावनाएँCresskill, न्यू जर्सी ।(हैम्पटन प्रेस : http://www.javnost-thepublic.org/media/datoteke/1998-2-dunaway.pdf। 2009-02- 15